

फ्रेडरिक एंगेल्स (1881)

मज़दूरी व्यवस्था

द लेबर स्टैंडर्ड अखबार के 21 मई, 1881 के अंक में प्रकाशित

पिछले एक लेख में हमने इस समयसिद्ध उक्ति पर विचार किया था, "काम के उचित दिन की उचित मज़दूरी", और इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि वर्तमान सामाजिक अवस्थाओं में काम के दिन की सबसे उचित मज़दूरी अनिवार्य रूप से मज़दूर के उत्पाद के सबसे अनुचित बँटवारे के समान होती है, उस उत्पाद का बड़ा हिस्सा पूँजीपति की जेब में जाता है, और मज़दूर को उतने से ही गुजारा करना पड़ता है जितने से वह खुद को काम करने लायक बनाये रख सके और अपनी नस्ल को बढ़ा सके।

यह राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक नियम है, दूसरे शब्दों में, समाज के वर्तमान आर्थिक संगठन का एक नियम है, जो कि कोर्ट ऑफ चांसरी सहित इंग्लैण्ड के सभी सामान्य और वैधानिक क़ानूनों से अधिक शक्तिशाली है। जब तक समाज दो विरोधी वर्गों में बँटा हुआ है — जिसमें एक ओर हैं, उत्पादन के सभी साधनों, ज़मीन, कच्चे माल, मशीनरी पर एकाधिकार रखने वाले पूँजीपति; और दूसरी ओर हैं, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से पूरी तरह वंचित मेहनतकश, जिनके पास अपनी काम करने की शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं होता; जब तक यह सामाजिक संगठन मौजूद है तब तक मज़दूरी का नियम सर्वशक्तिमान बना रहेगा, और हर दिन उन जंजीरों को और मज़बूत बनाता रहेगा जो मेहनतकश इंसान को खुद अपनी पैदावार का गुलाम बनाये रखती हैं — जिस पर पूँजीपति का एकाधिकार होता है।

इस देश की ट्रेड यूनियनों को इस क़ानून के खिलाफ़ लड़ते हुए अब करीब साठ साल हो गये हैं — और नतीजा क्या रहा? क्या वे मज़दूर वर्ग को उन बन्धनों से मुक्त कराने में सफल हुई हैं जिनमें पूँजी — खुद उसके हाथों की पैदावार — ने उसे बाँधा रखा है? क्या उन्होंने मज़दूर वर्ग के एक भी तबके को उजरती गुलामों की स्थिति से ऊपर उठने में, उत्पादन के साधनों का, कच्चे माल, औज़ारों, अपने उद्योग में आवश्यक मशीनरी का स्वामी, और इस तरह अपने श्रम की पैदावार का स्वामी बनने में सक्षम बनाया है? सब जानते हैं कि न केवल उन्होंने ऐसा नहीं किया है बल्कि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की है।

लेकिन इस नाते हम यह नहीं कह सकते कि चूँकि ट्रेड यूनियनों ने ऐसा नहीं किया है इसलिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसके विपरीत, इंग्लैण्ड में, और औद्योगिक उत्पादन करने वाले हर देश में, पूँजी के विरुद्ध मज़दूर वर्ग के हर संघर्ष में ट्रेड यूनियनों उसके लिए ज़रूरी हैं। किसी भी

देश में मजदूरी की औसत दर उस देश में आम जीवन स्तर के अनुसार मजदूरों की नस्ल को जिन्दा रहने के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं के योग के बराबर होती है। यह जीवन स्तर अलग-अलग श्रेणियों के मजदूरों के लिए अलग-अलग हो सकता है।

मजदूरी की दर ऊँची बनाये रखने और काम के घण्टे कम करने के संघर्ष में ट्रेड यूनियनों का बहुत बड़ा लाभ यह है कि वे जीवन स्तर ऊँचा बनाये रखने और उसे बेहतर करने में मदद करती हैं। लन्दन के पूर्वी भाग में बहुत से पेशे ऐसे हैं जिनका श्रम राजगीर मिस्त्रियों तथा राजगीर के साथ काम करने वाले मजदूरों से अधिक कुशल और उनके जैसा कठिन नहीं है, फिर भी वे इसके मुकाबले आधी मजदूरी ही कमा पाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक शक्तिशाली संगठन पहले वाले मजदूरों को तुलनात्मक रूप से ऊँचा जीवन स्तर बनाये रखने में सक्षम बनाता है जिससे उनकी मजदूरी निर्धारित होती है — जबकि दूसरे वाले मजदूरों को असंगठित और कमजोर होने के नाते अपने नियोक्ताओं के अपरिहार्य और मनमाने अतिक्रमण का शिकार होना पड़ता है; उनका जीवन स्तर लगातार गिरता जाता है, वे लगातार कम से कम मजदूरी पर जीना सीख लेते हैं, और उनकी मजदूरी स्वाभाविक रूप से उस स्तर तक गिर जाती है जिसे उन्होंने खुद पर्याप्त मान लेना सीख लिया है।

यानी, मजदूरी का नियम ऐसी रेखा नहीं खींचता जिसमें लचीलापन न हो। यह कुछ सीमाओं के साथ अटल नहीं है। हर समय (महामन्दी को छोड़कर) हर ट्रेड के लिए एक खास दायरा होता है जिसके भीतर दोनों विरोधी पक्षों के संघर्ष के परिणामस्वरूप मजदूरी की दर में संशोधन हो सकता है। हर मामले में मजदूरी का निर्धारण सौदेबाजी से होता है और सौदेबाजी में जो सबसे देर तक और सबसे अच्छी तरह प्रतिरोध करता है उसीके पास अपने देय से अधिक पाने का सबसे अधिक मौका रहता है। अगर कोई अकेला मजदूर पूँजीपति के साथ सौदेबाजी की कोशिश करता है तो वह आसानी से मात खा जाता है और उसे अपने आप समर्पण करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी पेशे के सभी मजदूर एक शक्तिशाली संगठन बना लेते हैं, अपने बीच से इतना कोष जमा कर लेते हैं जिससे वे ज़रूरत पड़ने पर अपने नियोक्ताओं के खिलाफ जा सकें, और इस प्रकार इन नियोक्ताओं से एक ताकत के तौर पर मुकाबला करने में सक्षम हो जाते हैं, तभी, और सिर्फ तभी, उन्हें वह थोड़ी-सी रकम मिल सकती है जिसे वर्तमान समाज के आर्थिक संगठन के अनुसार, काम के उचित दिन की उचित मजदूरी कहा जा सकता है।

ट्रेड यूनियनों के संघर्ष से मजदूरी का नियम पलट नहीं जाता। इसके विपरीत वे इसे लागू कराती हैं। ट्रेड यूनियनों के प्रतिरोध के बिना मजदूर को वह भी नहीं मिलता जो मजदूरी व्यवस्था के अनुसार उसे मिलना चाहिए। ट्रेड यूनियनों के डर से ही पूँजीपति को उसके मजदूर की श्रम शक्ति का पूरा मूल्य देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आपको सबूत चाहिए? बड़ी ट्रेड यूनियनों

के सदस्यों को मिलने वाली मज़दूरी देखिये, और दुख-तकलीफ़ से भरे उस गड्ढे लन्दन के उस पूर्वी इलाके में असंख्य छोटे-छोटे पेशों के कामगारों को मिलने वाली मज़दूरी को देख लीजिए।

इस तरह ट्रेड यूनियन मज़दूरी व्यवस्था पर हमला नहीं करतीं। लेकिन मज़दूरी कम या ज्यादा होने से मज़दूर वर्ग की आर्थिक अवनति नहीं होती। यह अवनति इस तथ्य में निहित होती है कि अपने श्रम की पूरी पैदावार प्राप्त करने के बजाय मज़दूर वर्ग को अपनी पैदावार के एक हिस्से से सन्तुष्ट होना पड़ता है जिसे मज़दूरी कहते हैं। पूँजीपति सारी पैदावार को हड़प लेता है (उसी में से वह मज़दूर का भुगतान करता है) क्योंकि श्रम के साधनों पर उसका मालिकाना होता है। और, इसलिए, जब तक मज़दूर वर्ग काम के सभी साधनों — ज़मीन, कच्चा माल, मशीनरी, आदि का — और इस प्रकार अपनी समस्त पैदावार का मालिक नहीं बन जाता तब तक वह वास्तव में मुक्त नहीं हो सकता।